पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

# यूपीए सरकार ने अगर बढ़ती मंहगाई न रोकी और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ी दरें वापस नहीं ली तो बसपा का केन्द्र के खिलाफ चरणबद्ध आन्दोलन–मायावती

## बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की केन्द्र को चेतावनी

## पूर्व की एनडीए तथा वर्तमान यूपीए दोनों सरकारें तेल की अव्यवस्था और मंहगाई के लिए बराबर की जिम्मेदार–बसपा अध्यक्ष

## डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमते बढ़ने से दलित गरीब मजदूर किसान तथा मध्यम वर्गों पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा–मुख्यमंत्री

**लखनऊ : 05 जून, 2008**

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने केन्द्र की यूपीए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने तेजी से बढ़ रही मंहगाई को नहीं रोका और कल पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के दामों में की गयी वृद्धि को वापस नहीं लिया तो उनकी पार्टी पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से केन्द्र की सरकार के खिलाफ आन्दोलन करेगी।

सुश्री मायावती ने कहा कि केन्द्र की मौजूदा अव्यवस्था तथा मंहगाई के लिए पूर्व की एनडीए एवं वर्तमान की यूपीए दोनों सरकारें बराबर की जिम्मेदार हैं, अब यह दोनों गठबन्धन लोगों का ध्यान बांटने के लिए एक–दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लगातार बढ़ती हुई मंहगाई तथा कल तेल एवं गैस की कीमतों में वृद्धि के लिए यूपीए को ही दोषी मानती है और इसकी घोर निंदा करती है।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने केन्द्र की सरकार से बसपा का समर्थन वापस लिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि अब यूपीए सरकार को कोई चेतावनी नहीं दी जायेगी बल्कि समय आने पर तुरंत कार्रवाई होगी, समर्थन वापसी के और भी मुद्दे हैं जिन पर उनकी पार्टी विचार–विमर्श कर निर्णय लेगी।

सुश्री मायावती आज नई दिल्ली में मीडिया प्रतिनिधियों से बात–चीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल के दौरान डीजल में लगभग 12 रूपये, पेट्रोल में लगभग 15 रूपये तथा घरेलू गैस की कीमतों में लगभग 78 रूपये की बढोत्तरी हुई है तथा रसोई गैस के नये कनेक्शन पर सिक्योरिटी की धनराशि में भी कुछ दिन पूर्व 500 रूपये प्रति कनेक्शन की दर से चुपचाप वृद्धि की गयी है। उन्होंने इस मूल्य वृद्धि को गरीब विरोधी बताते हुए यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले ने दलित, गरीब, वंचित, सहित मध्यम वर्ग को और मुश्किल में डाल दिया है तथा इस निर्णय से छोटे किसानों को कर्ज माफी के नाम पर गुमराह करने वालों का चेहरा उजागर हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने वाली यूपीए सरकार जो एक ओर यह मानती है कि खेती करना मुनाफे का काम नहीं रहा है, वहीं दूसरी ओर डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर और ज्यादा बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोत्तरी देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों पर और अधिक बोझ बढ़ायेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियों का ही यह परिणाम है कि पूंजीपति तथा धनाढ़य लोग उतने ही रूपयों में गैस खरीदेंगे, जितने में मध्यम वर्ग के लोग खरीदतें हैं, जिनकी सालाना आमदनी अमीरों के मुकाबले न के बराबर है, जिससे यूपीए सरकार की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये बनाई गई नीतियां पूरी तरह बेमानी नजर आती है।

बसपा सुप्रीमों ने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार तथा पूर्व की एनडीए सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में पिछले 20–25 सालों में अमीर ज्यादा अमीर हुये और गरीब ज्यादा गरीब हुये। देश में लगभग आठ प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का दावा करने वाली यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण मंहगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि से मंहगाई और भी तेजी से बढ़ेगी, विशेषकर खाद्यान्न की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि केन्द का कथन है कि उसने सीमा शुल्क घटा दिया है, जबकि यदि केन्द्र सरकार चाहती तो उसे समाप्त भी कर सकती थी। इसके साथ साथ वह उत्पाद शुल्क भी और घटा सकती थी, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित, वंचित तथा सर्वसमाज में गरीब, मजदूर, किसान एवं मध्यम वर्ग को राहत देने के लिये केन्द्र सरकार उच्चतम आय वर्ग की आमदनी पर इनकम टैक्स बढ़ा सकती थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अधिक मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों पर भी इन्कम टैक्स बढ़ाया जा सकता था, परन्तु ऐसा न करके केन्द्र ने दलित, वंचित तथा सर्वसमाज में गरीब, मजदूर, किसान एवं मध्यम वर्ग पर और अधिक बोझ डाल दिया है।

सुश्री मायावती ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से तेल की कीमत कम करने में सहयोग की अपेक्षा की है तथा बिक्री कर की दरें घटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बिक्री कर की दरें घटाकर तेल की कीमत कम करना इस समस्या का स्थायी हल नहीं है, जबकि तेल के उत्पादन, आयात, निर्यात, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क इत्यादि पर केन्द्र सरकार का पूरा नियन्त्रण है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र की वर्तमान और पिछली सरकारों ने तेल का उत्पादन अधिकांश सरकारी कम्पनियों से हटाकर निजी कम्पनियों को देकर देश के हित के विरूद्ध समझौता किया है। ये कम्पनियां देश में तेल की खोज का ठेका लेकर सरकारी मिली भगत से तेल खोज में जान बूझकर देरी करती हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का भी इंतजार करती हैं, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र की वर्तमान एवं पूर्ववर्ती, सरकारों ने तेल खोज का कार्य निजी क्षेत्रों में देकर जहां एक ओर भविष्य में तेल की उपलब्धता को निजी व विदेशी हांथों में सौंप दिया है,वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की नौकरियों में आरक्षण की सुविधा से वंचित करके काफी परिवारों की रोजी रोटी के साधन भी समाप्त कर दिये गये है।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार मंहगाई पर नियंत्रण रखने में विफल रही है तथा राज्य सरकारों पर दाम घटाने की जिम्मेदारी डालकर वह अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर घटिया राजनीति कर रही है तथा अपनी गलत आर्थिक नीतियों पर परदा डालने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल पर वैट लागू नहीं है बल्कि अन्य राज्यों की तरह इन पर केवल बिक्री कर ही चार्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 26 प्रतिशत सेल्स टैक्स निर्धारित है, वहीं देश के अन्य राज्यों – आन्ध्र प्रदेश में 33 प्रतिशत, बिहार में 27

प्रतिशत, कर्नाटक में 28 प्रतिशत, केरल में 29.01 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 28.75 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 28 तथा महामुम्बई में 28 प्रतिशत पंजाब में 27.50 प्रतिशत, राजस्थान में 28 प्रतिशत तथा तामिलनाडु में 30 प्रतिशत की दर पर वसूली की जा रही है। इसी तरह डीजल पर जहां उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया गया है, वहीं आन्ध्र प्रदेश में 22.25 प्रतिशत, केरल में 24.69 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 28.75 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 28 तथा महामुम्बई में 33 प्रतिशत और तमिलनाडु में 23.43 प्रतिशत की दर से वसूली की जा रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रदेश सरकार डीजल व पेट्रोल पर बिक्री की दरे कम करेगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर देखा जाये तो तुलनात्मक रूप से हमारे प्रदेश में बिक्री कर दरें पहले से ही कम है, फिर भी सर्वसमाज के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार सकारात्मक कदम उठायेगी।

—————————